

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : उत्पादक शिक्षा एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन

*डॉ. सरोज जांगिड़

शोध सार

शिक्षा की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें सरकारी और निजी दोनों उपकरणों को महत्व दिया गया है। साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था कृषि तथा उद्योगों पर आधारित है। शिक्षा को हमें इस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। कि यहां के सरकारी निजी दोनों प्रकार के उद्योगों को तकनीकी विशेष मिल सके साथ ही कृषि के लिए नवीन उपकरणों का कार्य करने में सक्षम कृषि विशेषज्ञ तैयार हो सके। भारत को विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचने के लिए शिक्षा के व्यवसाय कारण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसंधान पर भी बल देना आवश्यक है। जिससे नवीन प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके साथ ही औद्योगिक प्रशंसकों को तैयार करने के लिए कदम उठाए जाए इन सभी मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए-नए मार्ग सुलभ होते हैं। ग्रामीण कृषि ज्ञान का उपयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। विश्व के कुछ राष्ट्र जैसे अरब में मैक्सिको ब्राजील आदि में प्राकृतिक संपदाओं की प्रचुर भंडार हैं किंतु शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव में वह राष्ट्र अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसकी विपरीत स्विटजरलैंड जर्मनी तथा डेनमार्क में स्थापित प्राकृतिक साधन हैं किंतु अच्छी शिक्षा व्यवस्था के कारण उन राष्ट्रों ने सीमित संसाधनों का पूरा सदुपयोग करके उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया स आर्थिक विकास में शिक्षा का अप्रत्यक्ष योगदान यह है कि यह परिवार के आकार बचत सीमाओं को प्रभावित करता है। सही तरह से व्यवहार और कौशल में प्रत्यक्ष योगदान उत्पादकता बढ़ाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बीज शब्द : एनईपी, करिकुलम फ्रेमवर्क, विशेषज्ञों, कमेटियां।

प्रस्तावना

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के हिसाब से कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) तैयार हो गया है। इसके प्रकाशन की तैयारी चल रही है। एनईपी 2020 घोषित होने की तीसरी वर्षगांठ 29 जुलाई या उससे पहले एनसीएफ सामने आ सकता है। सभी 10 कक्षाओं की नई किताबें तैयार करने के लिए भी विषय विशेषज्ञों की पहचान कर ली गई है। एनसीएफ के घोषित होते ही किताबें तैयार करने की कमेटियां गठित होंगी। कक्षा 3 से 12 तक के लिए स्कूली शिक्षा में अब करीब 150 विषयों की किताबें बनाई जाएंगी। तैयारी है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के शुरुआती महीनों में नए एनईपी के हिसाब से कक्षा-3, 6 और 9 की पहली किताबें सामने आ जाएं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : उत्पादक शिक्षा एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन

डॉ. सरोज जांगिड़

पिछली नीति की तुलना में पांच गुना तेजी से काम

पिछली नीति 1986 में आई, किताबें 2008 तक आईं। इस बार 2020 में नीति, 2 साल में प्री स्कूल की बुक्स, 12 वीं तक का कोर्स पूरा। नीति दस्तावेज 'सार्थक' में 297 टॉस्क लिस्ट हैं। इसमें से एक-तिहाई पूर्ण, अगले एक तिहाई अंतिम चरण में, शेष दो साल में पूरे हो जाएंगे।

1. फाउंडेशन स्टेज (3 से 8 साल) किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं :

बाल वाटिका/प्री-स्कूल में बच्चों को जादुई पिटारे (53 किस्म के खेल-खिलौने, पोस्टर, बोर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक, प्लेइंग कार्ड) से पढ़ाई होगी। स्कूल बैग नहीं होगा। सभी सेंट्रल स्कूल में बाल वाटिका खोली गई हैं। जादुई पिटारा फरवरी में जारी हो चुका है। प्राइवेट स्कूलों में ही प्ले ग्रुप और नर्सरी की क्लासेस चलती हैं। अब एनईपी में शुरूआती तीन साल सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाए जाएंगे। 6 से 8 साल: प्री-स्कूलिंग कर चुके छह साल के बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। इसमें केवल दो किताबें होंगी भाषा और गणित। दूसरी कक्षा के बाद फाउंडेशन लेवल पूरा होगा। फाउंडेशन लेवल में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस स्टेज की किताबें उपलब्ध हैं। जन्म से 3 साल तक माता-पिता के लिए भी पहली बार अर्ली चाइल्डकेयर एजुकेशन सिलेबस (पालन-पोषण में क्या ध्यान रखें, क्या करें) तैयार हो चुका है, ये सिलेबस जल्दी ही जारी किया जाएगा।

2. प्रीप्रेटरी स्टेज (8 से 11 साल): 3 भाषाएं और गणित की पढ़ाई

कक्षा 3 में आठ साल के बच्चे को दाखिला मिलेगा। तीन भाषाएं और गणित की पढ़ाई होगी। 5 वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। कक्षा 3 में पहली बार बच्चे का मूल्यांकन होगा। कक्षा-5 के आखिर में दूसरी बार मूल्यांकन होगा।

3. मिडिल स्टेज (11 से 14 साल) : वोकेशनल एक्सपोजर शुरू होगा

कक्षा 6 में 11 साल के बच्चे को दाखिला मिलेगा। 8वीं कक्षा तक बच्चों को वोकेशनल एक्सपोजर कराया जाएगा, इसका मूल्यांकन नहीं होगा। भाषा और विज्ञान के अलावा मानविकी, विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान की बेसिक पढ़ाई करेंगे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने पर तीसरा मूल्यांकन होगा। कक्षा-3, 5 और 8 में होने वाले मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा की तरह नहीं होंगे। छात्रों-पैरेंट्स की नियमित काउंसलिंग होगी। वोकेशनल एजुकेशन का मूल्यांकन 9वीं कक्षा से होगा।

4. सेकंडरी स्टेज (14 से 18 साल): 9वीं का रिजल्ट 10 वीं में भी जुड़ेगा:

कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी। साल में बोर्ड परीक्षा के दो मौके मिलेंगे। 9वीं 10वीं और 11वीं-12वीं में कुल 16-16 पेपर (कोर्स) देने होंगे यानी एक साल में कम से कम 8 पेपर होंगे। 9वीं का रिजल्ट 10वीं के फाइनलसर्टिफिकेट में जुड़ेगा, इसी तरह 11वीं के अंक 12वीं के रिजल्ट में जुड़कर सर्टिफिकेट मिलेगा। 9 वीं व 10 वीं में आठ स्ट्रीम होंगे मानविकी व भाषा, मैथमेटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप इन 8 ग्रुप में हर से दो-दो यानी 16 पेपर चुनने होंगे। इन्हीं आठ समूहों में से न्यूनतम तीन समूहों से चार विषय चुनने होंगे। हर विषय के चार-चार पेपर होंगे। चुनने के 150 विकल्प मिलेंगे। अभी तक 11 वीं व 12 वीं के स्तर पर साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स संकाय हैं। लेकिन, अब संकाय का कोई विभाजन नहीं बचेगा। यहां तक कि संगीत, खेल व क्राफ्ट गतिविधियों को आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन व वोकेशनल एजुकेशन का दर्जा मैथमेटिक्स, साइंस, मानविकी, भाषा व सामाजिक विज्ञान के बराबर

होगा। रिपोर्ट कार्ड जो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहलाएगा, उसमें करिकुलर, को-करिकुलर सभी गतिविधियों में प्रदर्शन का ब्यौरा होगा।

अब तक क्या हो चुका: केंद्रीय विद्यालयों में प्री-स्कूल की कक्षाएं, टीचर्स को ट्रेनिंग

केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका प्री-स्कूल कक्षाएं स्थापित हो चुकी हैं। केवीएस एनवीएस के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सीबीएसई स्कूलों और गुजरात में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का पायलट प्रोजेक्ट टेस्ट हो चुका है। देश के 60 बोर्ड में एकरूपता के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर 'परख' की स्थापना हुई है। पीएम श्री स्कूलों के तहत मॉडल स्कूलों को विकसित कर रहे हैं।

भारत में नई शिक्षा नीति लागू: नर्सरी से लेकर पीएचडी तक में बदलाव।

भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने के बाद भारत की नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं:-

Five Years Fundamental

1. Nursery @ 4 Years
2. Jr KG @ 5 Years
3. Sr KG @ 6 Years
4. Std 1st @ 7 Years
5. Std 2nd @ 8 Years

Three Years Preparatory

6. Std 3rd @ 9 Years
7. Std 4th @ 10 Years
8. Std 5th @ 11 Years

Three Years Middle

9. Std 6th @ 12 Years
10. Std 7th @ 13 Years Std 8th @ 14 Years

Four Years Secondary

12. Std 9th @ 15 Years
13. Std SSC @ 16 Years
14. Std FYJC @ 17 Years
15. STD SYJC @ 18 Years

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : उत्पादक शिक्षा एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन

डॉ. सरोज जांगिड़

नई शिक्षा नीति की प्रमुख बातें:

- दसवीं बोर्ड खत्म।
- केवल कक्षा 12 की परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा कहा जाएगा।
- MPhil की डिग्री बंद कर दी जाएगी।
- उच्च शिक्षा डिग्री कोर्स 4 साल का।
- 5वीं तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही पढ़ाया जाएगा।
- बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा।
- पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा।
- 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा।
- वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी यानि कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी।
- 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स एक साल में MA कर सकेंगे।
- MA के छात्र अब सीधे PHD कर सकेंगे।

निष्कर्ष:

स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 फीसदी हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमितसमय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड अकेडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नैशनल एजुकेशनल साइटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45 हजार कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। स्पेशल भी होता है।

***प्राचार्य**
बीएसएन कॉलेज
बक्सवाला, सांगानेर, जयपुर (राज.)

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. बोरग डेलनपेनय " अण्डर स्टैंडिंग एजुकेशन रिसर्च", मेकग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क, 1958
2. दत्ता संजयय "शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम एवं व्यक्तित्व", जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर, संस्करण – 2005
3. फ्रेडरिक एल. विहटनी दि एलीमेन्ट्स ऑफ रिसर्च एशिया पब्लिशिंग हाउस, न्यूयार्क, 1961

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : उत्पादक शिक्षा एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन

डॉ. सरोज जांगिड़

4. गुडे एवं हॉटय "मैथडस इन सोशल रिसर्च", मैग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क 1962
5. गुड, वी. कार्टर और स्केट्स डी.ई., "मैथडस ऑफ रिसर्च", एप्लटन सेन्चुरी क्राफ्टस (इंक), न्यूयार्क, 1954.
6. कपिल एच. के. "अनुसंधान विधियाँ", एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, 1998
7. कपिल एच.के.य "सांख्यिकी के मूल तत्व, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, 2007
8. करलिंगर एफ. एन. फाउंडेशन ऑफ बिहेवरियल रिसर्च सेन्चुरी क्राफ्ट, न्यूयार्क, 2002
9. कुलश्रेष्ठ एस.पी.य "शिक्षा मनोविज्ञान", आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2008
10. क्रेच एवं क्रचफील्डय "थ्योरी एण्ड प्राब्लम्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी", मैग्राहिल पब्लिकेशन, न्यूयार्क 1948